जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 164 प्रभात कोटा, रविवार 30 मार्च, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ग्रीनलैण्ड व कैनडा ने अमेरिका को झिड़की पिलाई

अमेरिका के उपराष्ट्रपति, जो ग्रीनलैण्ड की यात्रा पर थे, उनकी ग्रीनलैण्ड के निवासियों ने एक तरह से पूरी अवहेलना की और बहुत ही ठण्डा स्वागत किया

- यहाँ तक की ग्रीनलैण्ड के निवासियों ने सशस्त्र सामना करने की कृतसंकल्पता दिखाई, अगर, अमेरिका ने ताकत के जोर पर, ग्रीनलैण्ड पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। अमेरिकी आधिपत्य की संभावना इसलिए भी ढीली पड़ी, क्योंकि ग्रीनलैण्ड के चारों तरफ समुद्र में, रूस व चीन दोनों देशों ने सैनिक जहाज व पनडुब्बियाँ मंडराने के लिए भेज दी थीं।
- कैनडा ने भी अमेरिका को खुली चुनौती दी, अमेरिका ने कैनडा से भेजे गये सामान पर, ड्यूटी में भारी बढ़ोतरी की धमकी दी। चुनौती का असर हुआ और राष्ट्रपति ट्रम्प ने कैनडा के प्र.मंत्री को गवर्नर कहने के स्थान पर, सम्मान सूचक तरीके से संबोधन करना शुरु किया।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मार्च। ग्रीनलैण्ड और डेनमार्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस और उनकी पत्नी को द्वीप पर दौरे के दौरान कड़ी झिड़की दी है, वहीं ट्रम्प, ने ओवल ऑफिस में आनन-फानन में बुलाई एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में ग्रीनलैण्ड पर कब्जा करने के अपने दावे को दोहराया। अब ट्रम्प कह रहे हैं कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका के अधीन होना पड़ेगा। इस क्षेत्र में रूसी और चीनी नौसेना के जहाजों का भारी जमावड़ा है और यह स्थिति अमेरिका के लिए भारी पड़ सकती है।

डेनमार्क और ग्रीनलैण्ड की प्रतिक्रियाओं के साथ-साथ कैनडा ने भी, कैनडा पर नियंत्रण के अमेरिका के प्रयासों तथा टैरिफ को खुली चुनौती दी है, जिससे अमेरिकियों को झटका लगा है। डॉनल्ड ट्रम्प ने अब कैनडा पर अपने दावों को त्याग दिया लगता है और नए प्रधानमंत्री को "गवर्नर कार्नी" कहने के बजाय, उनके आधिकारिक उपनाम से संबोधित किया।

दूसरी तरफ, इस आर्कटिक द्वीप को अपने राष्ट्र का हिस्सा बनाने के अमेरिका के रवैये के कारण ग्रीनलैण्ड के लोगों ने यात्रा पर आए अमेरिकियों का भारी तिरस्कार किया।

अमेरिका को उम्मीद थी कि ग्रीनलैण्ड यात्रा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति का उत्साहपूर्ण स्वागत होगा। उपराष्ट्रपति व उनकी पत्नी, स्थानीय इनुइट लोगों के वार्षिक स्लैड डॉग शो में सम्मिलित होकर द्वीपवासियों के साथ सांस्कृतिक संपर्क बढ़ाने वाले थे।

लेकिन इसके बजाय, इस "हाई पावर" दम्पति को बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया मिली और अंततः वो सांस्कृतिक कार्यक्रम और शो में भाग नहीं ले पाए। उनकी यात्रा, द्वीप के अलग-थलग हिस्से में स्थित एक अमेरिकी अंतरिक्ष स्टेशन के दौरे तक सीमित रह गई। वहाँ पर भी उनका स्वागत करने के लिए कोई स्थानीय व्यक्ति मौजूद नहीं था।

इस बीच, डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स रासमुसेन ने एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में स्पष्ट रूप से कहा कि डेनमार्क और ग्रीनलैण्ड की सरकारों को, द्वीप की यात्रा पर आए अमेरिकियों व यू.एस. अधिकारियों की "टोन" पसंद नहीं आई है। ग्रीनलैण्डवासियों ने यहाँ तक धमकी दी थी कि यदि अमेरिका द्वीप के बलपूर्वक अधिग्रहण के अपने प्रयासों को जारी रखता है तो वे सशस्त्र संघर्ष भी कर सकते हैं। ग्रीनलैण्डवासियों और डेनमार्क सरकार द्वारा ठंडी प्रतिक्रिया मिलने के बाद, उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस ने द्वीप पर वर्तमान प्रशासन के बारे में कुछ टिप्पणियाँ कीं, जिन्हें आपत्तिजनक कहा गया। वैंस ने कहा कि डैनमार्क को ग्रीनलैण्ड के प्रति अपना व्यवहार बदलना होगा।

विदेश मंत्री लार्स रासमुसेन ने कहा कि यदि अमेरिका द्वीप पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है और फिर बातचीत की मेज पर आ सकता है। सन् 1951 की एक संधि के तहत, अमेरिका को उचित विचार-विमर्श के बाद द्वीप पर कुछ सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की अनुमति है। जो भी परिणाम हों, नए अमेरिकी प्रशासन को धीरे-धीरे यह बात समझ में आने लगी है कि अन्य देशों के बारे में की गई उसकी लापरवाह टिप्पणियाँ और अन्य देशों की संप्रभुता के संबंध में लिए गए उसे एकतरफा निर्णयों को मात्र सतही टिप्पणियों से सुलझाया नहीं जा सकता। कैनडा और ग्रीनलैण्ड दोनों ने ट्रम्प प्रशासन को कड़ा झटका दिया है और उसने अनिच्छा से यह स्वीकार किया है कि दुनिया भर में अमेरिकियों को उतना पसंद नहीं किया जाता, जितना वे सोचते थे।

नेपाल में हालात सामान्य, कर्फ्यू हटाया

नई दिल्ली, 29 मार्च। नेपाल में अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं शनिवार को काठमांडू के पूर्वी हिस्से से कर्फ्यू हटा लिया गया। शुक्रवार को राजशाही समर्थकों व सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। शुक्रवार को राजशाही की पुनर्बहाली की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए और हालात उस समय उग्र हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने एक राजनैतिक दल के कार्यालय पर हमला कर दिया, वाहनों में आग लगा दी और दुकानों में लूटपाट की। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने संसद भवन की ओर मार्च कर रही भीड़, जो पथराव कर रही थी, को रोकने के बल प्रयोग किया। हिंसा में एक टीवी कैमरामैन और एक प्रदर्शनकारी सहित दो लोगों की मौत हो गई तथा 112 लोग घायल हो गए।

म्यांमार भूकंप, 1644 की मौत 344 घायल

नेपीदा, 29 मार्च। म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे फिर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। इस तरह 2 दिन में 5 से ज्यादा तीव्रता वाले तीन भूकंप आ चुके हैं। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में भारी तबाही हुई है। मौत का आंकड़ा 10 हजार से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने जताई है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, मरने वालों का आंकड़ा 1644 हो चुका है, जबकि 3,408 से ज्यादा लोग घायल हैं और 139 लोग लापता हैं।

अमेरिका की भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगाने की बात केवल "हौवा" निकली?

अर्थशास्त्रियों का मानना है, कुछ क्षेत्रों, जैसे वाहनों के स्पेयर पार्टस में निर्यात गिरेगा, पर, कई अन्य क्षेत्रों में नये विकल्प खुलेंगे, दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए

- अमेरिका के व्यापार व ट्रेड प्रतिनिधि ब्रैंडन लिंच व भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच चल रही इस मुद्दे पर बातचीत 29 मार्च को पूरी हो रही है तथा दोनों देशों का मानना है कि बातचीत प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे के हितों पर ध्यान रखते हुए हो रही है।
- उदाहरण के लिए, भारत ने अमेरिका के कृषि उत्पादन का भारत को निर्यात बढ़ाने की प्राथमिकता को ध्यान में रखा है, पर, दूसरी ओर भारत से निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादन, जैसे- फल, विशेषकर अनार व अंगूर को बढ़ाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया है, जो अमेरिका ने लगभग स्वीकार कर लिया है।

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 मार्च। अमेरिका ने 2 अप्रैल को अपने प्रमुख व्यापारिक सहयोगियों पर "रैसिप्रोकल टैरिफ" की नीति लागू करने की घोषणा की है, अब 2 अप्रेल एकदम पास आ गई है, और भारत दोराहे पर, आर्थिक उथल-पुथल के खतरे और अप्रत्याशित अवसरों, के बीच में खड़ा है। खतरे की चेतावनी देने की बजाय विशेषज्ञ तर्क दे रहे है कि भारत इस संकट से न केवल बिना किसी नुकसान के बाहर निकल आएगा, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और निर्यात को बढ़ाने के नए रास्ते मिलेंगे।

नीति आयोग के अनुसार, प्रस्तावित अमेरिकन टैरिफ का टारगैट कुछ चुनिंदा सैक्टर्स ही होंगे, जिससे भारतीय निर्यात को स्थिति का लाभ उठाने के भारी अवसर मिलेंगे। आयोग के प्रोग्राम डायरेक्टर प्रवकार साहू ने नीति आयोग की तिमाही पुस्तिका "ट्रैड वॉच" के दूसरे संस्करण के विमोचन पर कहा, हम डेटा का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं और शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि भारत को इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा। रैसिप्रोकल टैरिफ सिर्फ कुछ सैक्टर को ही प्रभावित करेगा और इससे हमारे निर्यात का विस्तार करने के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।"

नीति आयोग के सदस्य अरविंद वर्मा ने इस आशावादी नजरिए का समर्थन किया। उन्होंने 2018 के एक मामले का हवाला दिया, जब अमेरिकन आयात में चीन की हिस्सेदारी कम हो गई थी, तब इससे ताईवान वियतनाम - थाइलैंड, मैक्सिको व भारत के निर्यात में भारी वृद्धि हुई थी। उन्होंने कहा कि एतिहासिक रुप से टैरिफ ने उन देशों के लिए नए द्वार खोले हैं, जो इस खाली जगह को भरने में सक्षम हैं।

आसन्न टैरिफ खतरे के बावजूद, भारत ने एक सक्रिय रुख अपनाया है, तनाव को कम करने के लिए अमेरिका को महत्वपूर्ण रियायतें दी हैं। सरकारी स्रोतों के अनुसार, भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कटौती का प्रस्ताव दिया है, जिसमें बादाम, क्रैनबेरी, बोरबॉन व्हिस्की, अखरोट, पिस्ता और दालें शामिल हैं। सबसे उल्लेखनीय कटौती बोरबॉन व्हिस्की पर की गई थी, जिसमें शुल्क 150 प्रतिशत से घटकर 100 प्रतिशत हो गया।

कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है, जबकि दालों पर लगभग 10 प्रतिशत शुल्क लगता है। हालांकि, डेयरी उत्पाद, चावल, गेहूं और मक्का के मामले में गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि भारत इन संवेदनशील क्षेत्रों पर सुरक्षात्मक बाधाओं को बनाए रखना चाहता है। नई दिल्ली में चल रही व्यापार वार्ताओं में अमेरिका का नेतृत्व सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (दक्षिण और मध्य एशिया) ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये वार्ताएं आज (शनिवार) को समाप्त होंगी।